









# क्या मायावती अपनी पार्टी को खत्म करने पर तुली हैं?

### अजय कुमार

बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपनी कुछ राजनैतिक जिम्मेदारियां अपने भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय को-ऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सौंप कर क्या संदेश दिया है, कोई नहीं जानता। मायावती ने अपने आप को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक समेट कर बाकी राज्यों की जिम्मेदारी आनंद को दे दी है। मायावती के इस फैसले पर नेतागण अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ को लगता है कि मायावती ने काफी सोच समझकर बसपा में अपने आप को सीमित किया है। संभवतः वह नहीं चाहती होंगी कि देश जीतने के चक्रर में कहीं उनका मजबूत किला यूपी और उत्तराखंड हाथ से नहीं निकल जाये। जहां उनके लिये हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं। कहा यह जा रहा है कि बहनजी चुनाव की तारीख घोषित होते ही यूपी में अपनी जनसभाएं शुरू कर देंगी। पहले वह मंडलवार सभाएं करेंगी। बीएसपी के लिये मजबूत समझी जाने वाली सीटों पर विशेष तौर पर फोकस रहेगा। मजबूत समझी जाने वाली सीटों के लिये वह जनसभाएं भी ज्यादा करेंगी।

चुनाव की बेला में मायावती ने जो कदम उठया है उससे बसपा को कितना नफा-नुकसान होगा यह तो समय ही बतायेगा, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो ने जो भी फैसला लिया है, वह काफी सोच समझकर लिया होगा। मायावती एक परिष्क नेत्री हैं। उन्होंने बसपा को इस बुलंदी तक पहुंचाने में पूरा योगदान दिया था। दलित चिंतक स्वर्गीय काशीराम की राजनैतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाली मायावती की पहचान एक बड़ी नेत्री के रूप में होती है। मायावती पर दलित पूरा विश्वास करते हैं। दलित वोटरों ने कभी भी बहनजी का साथ नहीं छोड़ा जबकि मायावती अपनी सियासी जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर गैर दलित वोटरों को भी बसपा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देती रही। बसपा की सियासी प्रयोगशाला से मायावती ने कभी दलित-मुस्लिमों को एक छतरी के नीचे खड़ा किया तो कभी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की राजनीति को अमली जामा पहनाया। मायावती ने दलित नेताओं की बड़ी लीडरशिप तैयार की तो कई क्षत्रिय,

ब्राह्मण, पिछड़ों और मुस्लिम चेहरों को भी राजनीति में उभरने का पूरा मौका दिया, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी रहा कि बसपा सुप्रीमो ने भले ही नये नेताओं की ‘फौज’ तैयार की थी, लेकिन यह नेता मायावती के साथ लम्बे समय तक रह नहीं पाये। इसमें से ज्यादातर को बहनजी ने स्वयं पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था तो कुछ ने मौके की नजाकत को भांप कर स्वयं पार्टी छोड़ने में देरी नहीं की। वैसे यह यह बताया भी गलत नहीं होगा कि मान्यवर कांशीराम ने सिर्फ मायावती को ही आगे नहीं बढ़ाया था। अलग-अलग समाज के लोगों को चुनकर उन्हें नेता बनाया था। ओमप्रकाश राजभर, सोनेलाल पटेल, आरके चौधरी और मसूद अहमद ऐसे ही नेताओं में शामिल रहे हैं लेकिन सभी बिछड़ते गए। राजभर ने २००२ में, दिवांगत सोनेलाल पटेल ने १९९५ में और आरके चौधरी ने २०१६ में बसपा छोड़ दी थी। आरके चौधरी तो राजनीति में कोई जगह हासिल नहीं कर पाए लेकिन ओमप्रकाश राजभर और सोने लाल पटेल की पार्टी आज भी अच्छी खासी राजनीतिक ताकत रखती हैं।

बसपा को जमीन से उठारकर आसमान तक ले जाने वाली मायावती की राजनीति पिछले दस वर्षों से काफी उतार पर नजर आ रही है। २००७ के विधानसभा चुनाव में वह अंतिम बार बड़े अंतर से सपा से जीती थीं। आज की तारीख में बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी के कई दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी हैं। इनमें कई ऐसे भी नाम हैं, जिन्हें एक समय मायावती का सबसे करीबी नेता माना जाता था। इनमें लालजी वर्मा न सिर्फ विधानमंडल दल के नेता थे बल्कि वर्मा वह नेता हैं, जिनके प्रदेश अध्यक्ष रहते २००७ में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में बनी थी। राम अचल राजभर भी मायावती के खासम खास माने जाते रहे हैं। १३ सालों में बसपा २०६ विधायकों से महज एक विधायक पर आ टिकी है। बसपा के जिन नेताओं को प्रदेश स्तर पर पहचान हासिल हुई थी वह एक-एक करके बसपा से अलग हो गए हैं। २००७ में जब प्रदेश में बसपा की बहुमत की सरकार बनी थी तब मायावती ने जितने विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया था, उनमें से आज एक्का-टुक्का ही बसपा के साथ खड़े हैं। २००७ में २०६



सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली मायावती ने नकुल दुवे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, लालजी वर्मा, रामवीर उपाध्याय, ठाकुर जयवीर सिंह, सुधीर गोयल, स्वामी प्रसाद मौर्य, वेदराम भाटी, चौधरी लक्ष्मी नारायण, राकेश धर त्रिपाठी, बाबू सिंह कुशवाहा, फागू चौहान, दहू प्रसाद, राम प्रसाद चौधरी, धर्म सिंह सैनी, राम अचल राजभर, सुखदेव राजभर और इंद्रजीत सरोज को बड़े पोर्टफोलियो दिए थे, लेकिन आज इसमें से कोई भी बसपा में नहीं है। सबसे अपनी अलग राह पकड़ ली है।

२०१२ में समाजवादी पार्टी चुनाव जीती और मुलायम ने अपने बेटे अखिलेश को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। उसके पश्चात २०१७ में बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुए। २०२२ में भी उनको जीत हासिल हुई और एक बार फिर वह सीएम बने। लेकिन मायावती का कहीं से कोई भला नहीं हुआ। २००७ में चुनाव जीतकर सरकार बनाने के बाद से उनकी सत्ता में वापसी भी नहीं हुई है जबकि अपनी ताकत बढ़ाने के लिये मायावती ने २०१९ में अपनी धुर विरोधी समाजवादी पार्टी तक से हाथ मिला लिया। परिणाम स्वूपर उनके दस सांसद चुनाव जीते थे, लेकिन अब यह सांसद भी बसपा से दूरी बनाने लगे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कहा, पार्टी बदलना मेरे लिए समस्या की जरूरत थी। मैं समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गया हूं और अब यह मेरा कर्तव्य है कि पार्टी को मजबूत करूं

# राजनीति और अपराध का खतरनाक गठजोड़

### अमेश चतुर्वेदी

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद इसे सिर्फ आपराधिक मामले की तरह देखे-सुने जाने की कोशिश होगी। लेकिन शाहजहां शेख का मामला सिर्फ आपराधिक नहीं है, बल्कि यह राजनीति के अपराधीकरण की समस्या की ओर भी ध्यान दिलाता है। समूचे देश के छोटे राजनीतिक दलों की ओर नजर दौड़ाए, अपराध और राजनीति का गठजोड़ जितना वहां सहज तरीके से दिखेगा, वैसा नजारा भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े दलों में कम ही दिखता है। छोटे दलों वाली राजनीति अपराधियों के स्थानीय रसूख के दम पर समर्थन हासिल करती है, इसी समर्थन के दम पर वह संवैधानिक ताकत हासिल करती है एवं फिर वह अपने क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि और राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित हो जाती है। चूंकि इस प्रक्रिया में अपराधी सबसे बड़ा औजार बन राजनीतिक दल के साथ खड़ा रहता है, इसलिए वह बदले में ताकत, पद आदि भी हासिल करने की कोशिश करता है। बिहार के शहाबुद्दीन रहे हों या मुग़िल तिवारी या उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद, उन्हें छोटे और स्थानीय दल रास आते रहे। राजनीतिक छतरी में उनका कारोबार फलता-फूलता रहा।

साठ-सतर के दशक तक अपराधी राजनीति को बूथ लूटने, वोटरों को धमकाने, उन्हें प्रकरांतर से समझाने के काम आते रहे। बदले में वे कुछ ठेके और आर्थिक फायदे ही हासिल करते रहे। बाद में जब अपराधियों को लगने लगा कि जब उनके दम पर पार्टी संवैधानिक पद हासिल कर सकती है, चुनाव जीत सकती है, तो वे खुद सीधे क्यों नहीं राजनीति में आ सकते। इसके बाद बिहार में सूरजदेव सिंह, काली पांडे, सूरजभान, शहाबुद्दीन जैसे लोग उभरे। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, हरिशंकर



तिवारी, वीरेंद्र प्रताप शाही, धनंजय सिंह जैसी राजनीतिक ताकतें उभरीं। अंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम जगहों पर ऐसे अपराधियों की

लंबी सूची बन गयी। वामपंथी दलों का दावा रहा है कि वे नैतिकता की राजनीति कुछ ज्यादा ही गहराई से करते रहे हैं। भारतीय राजनीति के लोकवृत्त यानी पब्लिक स्फ़ीयर में जो मूल्य स्थापित हुए हैं, उनमें से ज्यादातर की सूत्रधार वामपंथी राजनीति रही है। लेकिन इसी राजनीति का स्याह पक्ष पश्चिम बंगाल की राजनीति भी रही है, जहां की राजनीति में एक दौर में अपराधियों का बोलबाला था, जिन्हें वाममोर्चा की सत्ता की छांव मिलती रही। जिसने भी वामपंथी राजनीति के इस भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर सवाल उठाने की कोशिश की, उसे मुंह की खानी पड़ी। मारपीट तो बंगाल की राजनीति का स्थायी भाव रही। ममता बनर्जी ने इस पर लगाम लगाने का वादा जरूर किया, लेकिन जब उसे पूरा करने का वक आया, तो वे भी बदलने लगे। यही वजह है कि वहां शाहजहां शेख जैसे नेता उभरने लगे।

राजनीति और अपराधियों के गठजोड़ पर पहली बार १९९३ में तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव एएन वोहरा समिति ने विचार किया था। लेकिन उस रिपोर्ट पर किसी सरकार ने कार्रवाई नहीं की। सुप्रिम कोर्ट में उस रिपोर्ट को जांच एजेंसियों को देने की मांग को लेकर २००० में याचिका डाली गयी। पर सुप्रिम कोर्ट इस मांग को पूरा नहीं कर

पाया। इस रिपोर्ट को अब तक सर्वजनिक तक नहीं किया गया है। वह तो भला हो सुप्रिम कोर्ट का, कि उसने चुनावों में उम्मीदवारों के लिए अप्रीम और अपने पति या पत्नी की संपत्ति की घोषणा करना और अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों का हलफनामा जमा करना जरूरी बना दिया। बेशक जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत किसी सांसद की सांसदी और विधायक की विधायकी तभी खत्म होती है, जब जन प्रतिनिधि को तीन साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है। इसे कानून की खामी ही कहेंगे कि अपराधी कहे जाने लोग भी चुनाव लड़ जाते हैं और कई बार उसकी राबिन्हुड़ी छवि, तो कई बार खराब सम्मान में उन्हें अपना समर्थन दे डालते हैं। राजनीतिक समर्थन हासिल करने के बाद वह आपराधिक व्यक्ति जैसे गंगा में नहा उठता है।

हमारा समाज भी ऐसा है कि अतीत में जिसे सजा हो चुकी होती है, यदि वह जोड़तोड़ से कोई पद हासिल कर लेता है, उसे दुनिया अपनी नजरों पर उठा लेती है। राजनीति तो हमेशा समर्थन के लिए लालायित रहती है, इसीलिए वह अपराधियों को खुद से दूर नहीं करना चाहती। लेकिन जब उस आपराधिक व्यक्तित्व के चलते राजनीति की अपनी दुनिया प्रभावित होने लगती है, तो उससे पीछे छूड़ने और उससे अपना रिश्ता तक दिखाने से राजनीति भाग खड़ी होती है। यह सब वह पापमुक्त होने के लिए करती है। शाहजहां शेख को तुणमूल कांग्रेस की सदस्यता से बर्खास्त किया जाना राजनीति की उसी रव्यात का एक उदाहरण है। शाहजहां शेख के मामले ने राजनीतिक दलों के सामने एक चुनौती छोड़ी है कि क्या कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं हो सकता, जो २२ कैरट टोस नैतिकता की राजनीति करे, अपराधियों को किसी भी कीमत पर खुद से दूर रख सके और राजनीति को साफ-सुथरा रखने के लिए खुद और अपने कार्यकर्ताओं पर ज्यादा भरोसा रखे। फिलहाल तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है।

# परिवारवाद बनाम मोदी का परिवार की लड़ाई में आगे कौन ?

### अकि्त सिंह

परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए भाजपा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्षी दलों पर निशाना साधते रहते हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट के लिए बांसुरी स्वराज की उम्मीदवारी के बाद विपक्ष को भाजपा और मोदी पर पलटवार करने का मौका मिल गया है। बांसुरी स्वराज पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुषमा स्वराज की बेटें हैं। भाजपा ने पार्टी के निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि हमारी पार्टी कैडर आधारित है जो उम्मीदवारों के चेहरे पर नहीं बल्कि कैडर की ताकत पर चुनाव लड़ती है। हालांकि, विपक्ष इसे धुनाने की कोशिश में लगा हुआ है। ये सब तब हो रहा है कि मोदी के परिवार पर लालू यादव के एक बयान में राजनीतिक चर्चा तेज कर दी है।

पीएम मोदी अक्सर वंशवाद की राजनीति पर वार करते रहते हैं। वहीं, विपक्ष का दावा रहता है कि भाजपा में भी परिवारवाद है। विपक्ष का दवा रहता है कि राजनाथ सिंह और उनके बेटे एक साथ राजनीति में हैं। राजनाथ सिंह जहां सांसद और रक्षा मंत्री हैं तो वहीं उनके बेटे पंकज सिंह नौएडा से विधायक हैं। इसके अलावा विपक्ष नारायण राणे का भी नाम लेता है जो केंद्र में मंत्री हैं उनके बेटे नितिश राणे भाजपा के विधायक है। विपक्ष की ओर से धर्मंद प्रधान और पीयूष गोयल का भी नाम लिया जाता है। दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल और मां चंद्रकांता गोयल भी भाजपा से जुड़ी रही हैं। धर्मंद प्रधान के पिता देबेंद्र प्रधान भी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही विपक्ष का दावा रहता है कि अगर मोदी और भाजपा को परिवारवाद से दिक्रत है तो उसने ऐसी पार्टियों से गठबंधन क्यों किया है जिनमें परिवारवाद हावी है। इसको लेकर विपक्ष की ओर से जीतन राम माझी की पार्टी और रामविलास पासवान की पार्टी का हवाला दिया जाता है।



हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि एक परिवार को कई पीढ़ियों के सदस्य यदि योग्यता से राजनीति में आते हैं तो वह उसे परिवारवाद नहीं मानते बल्कि एक ही परिवार द्वारा पार्टी चलाने को गलत मानते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक परिवार के आगे कुछ नहीं दिखाई देता और इससे उसने खुद का, विपक्ष का, देश का और संसद का बड़ा नुकसान कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि देश को अच्छे, स्वस्थ विपक्ष की बहुत जरूरत है, लेकिन कांग्रेस ने दस साल के बाद भी स्वस्थ विपक्ष बनने का प्रयास नहीं किया। मोदी ने परिवारवाद को लेकर भाजपा के बयानों पर आने वाली प्रतिक्रियाओं का जवाब देते हुए कहा, “आज में परिवारवाद का मतलब समझा देता हूं। अगर किसी परिवार के एक से अधिक लोग जन समर्थन से अपने बलबूते राजनीतिक क्षेत्र में प्रगत करते हैं तो उसे हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा।” उन्होंने कहा, “हम किसी पार्टी को एक ही परिवार द्वारा चलाये जाने, परिवार के लोगों को ही प्राथमिकता मिलने, परिवार के लोगों द्वारा ही सारे निर्णय लिया जाने को परिवारवाद मानते हैं।” मोदी ने सदन में सत्ता पक्ष की अग्रिम पंक्ति में अपने पास बैठे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की ओर इशारा करते हुए कहा, “न राजनाथ जी का कोई राजनीतिक दल है, न अमित शाह का कोई राजनीतिक दल है।” विपक्ष पर वार करते हुए मोदी

बार-बार कह रहे कि वो कहते हैं – परिवार फर्स्ट, मोदी कहता है –राष्ट्र फर्स्ट। उनके लिए उनका परिवार भी सबकुछ है। मेरे लिए देश का हर परिवार सबकुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देशहित को बलि चढ़ा दिया। मैंने देशहित के लिए खुद को खपा दिया है।

नरेंद्र मोदी की ओर से पूरे देश को अपना परिवार बत्राए जाने के कुछ देर बाद सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के ‘प्रोफाइल’ पर अपने नाम के आगे ‘मोदी का परिवार’ लिखा और इस संबंध में एक अभियान शुरु कर दिया। एक दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पटना में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी पर ‘अपना परिवार’ नहीं होने को लेकर कटाक्ष किया था। इसके बाद भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की समर्थन में यह अभियान चलाया। लालू ने एक रैली में कहा था, “अगर नरेंद्र मोदी के पास अपना परिवार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। वह राम मंदिर के बारे में डींगें मारते रहते हैं। वह सच्चे हिंदू भी नहीं हैं। हिंदू परंपरा में बेटे को अपने माता-पिता के निधन पर अपना सिर और दाढ़ी मुंडवानी चाहिए। जब मोदी को मां की मृत्यु हुई तो उन्होंने ऐसा नहीं किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए हाल में ही कहा था कि ‘इंडिया’ गठबंधन सभी वंशवादी पार्टियों का गठबंधन है। सोनिया गांधी का लक्ष्य राहुल गांधी को पीएम बनाना है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी सीएम बन जाएं। लालू यादव का मकसद भी अपने बेटे को सीएम बनाना है। इसी तरह से एमके स्टालिन भी चाहते हैं कि उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के सीएम बनें। मुलायल सिंह तो अपने बेटे को सीएम बनाकर ही गए हैं।





